



EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

The SCAT India TradeShow 2023 is all set to open at the Jio World Convention Centre from October 8 -10, 2023. The Show promises to again showcase the latest trends and technologies in the broadband, cable TV and IPTV and satellite segment. Make sure all of you attend the Trade show and see the brands launching new products.

The SCAT industry is witnessing a rapid change and seeing new developments in terms of policy change initiatives from the Govt and also tech innovation. Both of these changes will drive a transformation in this sector.

The recent TRAI new directive for the implementation of DRM with the consultation undertaken to prepare the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual. The Draft Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 was issued on 27.08.2019 which included issues related to Digital Rights Management Systems.

The IPTV-based DPOs are switching to DRM technology and the Audit regime covers the DRM based networks and provides for enabling provisions for such operators. The Authority received numerous comments and suggestions from various stakeholders on this issue. Numerous modification/additions were proposed by several stakeholders

The Telecom Regulatory Authority of India is planning to bring out a consultation paper for matters related to OTT players. TRAI mooted the idea of I&B Ministry overseeing the content regulation and the Electronics & Information Technology Ministry handling the carriage part.

TRAI is also planning to discuss price parity between OTT video platforms and distribution channels like cable TV and DTH services. Live content on OTT can be brought under rules similar to the broadcasting sector.

BARC has fixed the price for Respondent Level Data at Rs 15 lakh per annum for the broadcasters. This should make life easier for the broadcasters and usher in transparency in the TV channel TRP ratings.

DD Free Dish has been under fire from AIDCF – the All India Digital Cable Federation) which has moved the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) against DD Free Dish for allegedly not abiding by TRAI's regulation that requires the channels to be provided in an encrypted manner.

The cable federation urged the tribunal to ensure that all private television channels are broadcast to the end consumer in encrypted form through digital addressable systems.

The doyen of broadcasting – Rupert Murdoch has finally handed over the mantle to his son. At the age of 92, media mogul Rupert Murdoch is stepping down as chairman of Fox Corporation and News Corp but will stay on in the role of chairman emeritus, presumably to help guide his eldest son Lachlan as the new head of the firm.

(Manoj Kumar Madhavan)

स्कैट इंडिया ट्रेड शो 2023, 8 से 10 अक्टूबर 2023 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह शो ब्रॉडबैंड, केबल टीवी और आईपीटीवी और सैटेलाइट सेगमेंट में नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों को फिर से प्रदर्शित करने का वादा करती है। सुनिश्चित करें कि आप सभी ट्रेड शो में शामिल हों और ब्रांडों को नये उत्पाद लॉन्च करते हुए देखें।

स्कैट उद्योग तेजी से बदलाव देख रहा है और सरकार की ओर से नीतिगत बदलाव की पहल और तकनीकी खोज के संदर्भ में नये विकास देख रहा है। ये दोनों परिवर्तन इस क्षेत्र में बदलाव लायेंगे।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल तैयार करने के लिए किये गये परामर्श के साथ डीआरएम के कार्यान्वयन के लिए ट्राई का यह हालिया निर्देश है। ड्रॉफ्ट टेलीकम्युनिकेशन (प्रसारण और केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (संशोधन) विनियम, 2019 को 27.08.2019 को जारी किया गया था जिसमें डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

आपीटीवी आधारित डीपीओ डीआरएम तकनीकी पर स्विच कर रहे हैं और ऑडिट व्यवस्था डीआरएम आधारित नेटवर्क को कवर करती है और ऐसे ऑपरेटों के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करती है। प्राधिकरण को इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए। कई हितधारकों द्वारा कई संशोधन/परिवर्धन प्रस्तावित किये गये थे।

एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ओटीटी कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए एक परामर्श पत्र लाने की योजना बना रहा है। ट्राई ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सामग्री विनियमन की देखरेख करने और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कैरिज हिस्से संभालने का विचार दिया है।

ट्राई ओटीटी वीडियो प्लेटफॉर्म और केबल टीवी और डीटीएच सेवाओं जैसे वितरण चैनलों के बीच मूल्य समानता पर भी चर्चा करने की योजना बना रहा है। ओटीटी पर लाइव कंटेंट को प्रसारण क्षेत्र के समान नियमों के तहत लाया जा सकता है।

वीएआरसी ने प्रसारकों के लिए प्रतिवादी स्तर के डेटा की कीमत 15 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की है। इससे प्रसारकों के लिए जीवन आसान हो जायेगा और टीवी चैनलों की टीआरपी रेटिंग में पारदर्शिता आयेगी।

डीडी फ्री डिश एआईडीसीएफ - (ऑल इंडिया डिजिटल फेडरेशन) के निशाने पर है, जिसने कथित तौर पर ट्राई के नियमों का पालन नहीं करने के लिए डीडी फ्री डिश के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपील न्यायाधिकरण (टीडीसैट) का रुख किया है, जिसके लिए चैनलों को एन्क्रिप्टेड तरीके से उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है।

केबल फेडरेशन ने ट्रिब्यूनल से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि सभी निजी टेलीविजन चैनल डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से एन्क्रिप्टेड रूप में अंतिम उपभोक्ताओं तक प्रसारित किये जायें।

प्रसारण के पुरोधा-रुपर्ट मरडोक ने आखिरकार कार्यभार अपने बेटे को सौंप दिया है। 92 साल की उम्र में मीडिया मुगल रूपर्ट मरडोक फॉक्स कॉरपोरेशन और न्यूज कॉर्प के अध्यक्ष पद से हट रहे हैं, लेकिन संभवतः अपने बड़े बेटे लाचलान को फर्म के नये प्रमुख के रूप में मार्गदर्शन करने मदद करने के लिए वे एमेरिटस अध्यक्ष की भूमिका में बने रहेंगे।

(Manoj Kumar Madhavan)